

बिहार विधान सभा वादवृत्त

सोमवार, तिथि १ अक्टूबर, १९५१

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य-विवरण ।
सभा का अधिवेशन पटने के राज्यपाल भवन में सोमवार, तिथि १ अक्टूबर, १९५१ को
पूर्वाह्न ८ बजे माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर ।

Short Notice Questions And Answers.

गया जिला के नवादा सबडिवीजन के हसुआ याना अन्तर्गत
पंचाने नदी में पुल बांधा जाना ।

२६। श्री यमुना प्रसाद सिंह—क्या माननीय मंत्री, स्वायत्त-शासन विभाग, यह बताने
की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या सरकार को मालूम है कि गया जिला के नवादा सबडिवीजन के हसुआ
याना अन्तर्गत नारदीगंज के पास पंचाने नदी में एक पुल बांधने का काम आज से १०-१२
वर्ष पहले मुजफ्फरपुर के बटलर साहब को ठीका दिया गया था ;

(ख) यह पुल कब और कितने रुपये में ठीका दिया गया था ;

(ग) पुल निर्माण का काम कब और क्यों बन्द हुआ ;

(घ) पुल निर्माण के ताल्लुक गया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और बटलर साहब के बीच कोई
मुकदमा हुआ था ;

(ङ) यह मुकदमा कब, क्यों और कितने दिनों तक चलता रहा तथा हाई कोर्ट का
क्या फैसला हुआ ?

माननीय पंडित विनोदानन्द झा—(क) और (ख) यह काम मुजफ्फरपुर के मेसर्स
आरथर बटलर एंड को० को ठीका दिया गया था और सट्टा १९३९ के जुलाई में
६८,६३५) ९० में उनके कोटेशन के मुताबिक लिखा गया था ।

(ग) अर्थभाव के कारण डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन के हुक्म से १९४० के अक्टूबर
में काम रोक दिया गया ।

(घ) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(ङ) मेसर्स आरथर बटलर को० ने मुजफ्फरपुर के सब-जज के यहाँ १९४२ में
काम में ज्यादा खर्च होने पर मनी-सूट दायर किया । थोड़े दिनों के बाद उस कम्पनी
ने हाई कोर्ट में अपील की कि हाई-कोर्ट इस बात का फैसला करे कि इस मुकदमे की
कार्रवाई कहाँ होनी चाहिए । हाई-कोर्ट ने फरवरी १९४८ में फैसला किया कि इसकी
कार्रवाई गया में होनी चाहिए । इस मुकदमे का फैसला गया की कचहरी में १२ सितम्बर
१९४६ में हुआ जिसमें मेसर्स आरथर बटलर एंड को० की हिकी हुई ।

(e) (i) The position has been explained and the reply is covered by replies to parts (c) and (d) above.

(ii) and (iii) The questions do not arise. In view of the high costs of construction it is not possible to adhere any further to the standard of accommodation or to the type of quarters fixed up several years ago. Austerity measures have been adopted for all types of constructions and every officer is required to put up with some personal inconvenience in view of the difficult situation. Since the realisation of rent is not dependent on the extent of accommodation available, the question of any injustice or harassment to the poorly paid Government servant does not arise. Every Government servant in occupation of Government accommodation, is required to pay a fixed percentage of his salary except in case where the standard rent of the accommodation given is less than that percentage.

ELECTRIC AND WATER CHARGES FROM THE NON-GAZETTED GOVERNMENT SERVANTS.

94. Shri NANDKISHORE NARAYAN LAL : Will the Hon'ble the Minister in charge of P. W. D. be pleased to state—

(a) in view of the reply given to clause (c) of starred question no. 1112, dated 25th April, 1951 stating that charges for electric, sanitary and water-supply installation will not be recovered from the non-gazetted Government servants who are paying 10 per cent rent will the Hon'ble Minister in charge of P. W. D. be pleased to state the date from which the above order will come into force ;

(b) whether Government consider the desirability of passing orders for the refund of the electric installation charges already realised from such Government servants from the year 1949, if not, the reasons for the same ?

The Hon'ble Shri ABDUL QUAYUM ANSARI : (a) While replying to question no. 1112, dated 25th April, 1951, it was mentioned that the revision of this rule has been taken up. Being a financial matter it was under examination but it was said that it is proposed to remove the discrimination. The revised rules are being provided in the Bihar Service Code in supersession of the existing B. & O. Service Code. After the publication of the revised rule the date from which the order will be given effect to, will be finalised. It is not likely that the orders will be given retrospective effect.

(b) As it is unlikely that the orders will be given retrospective effect the question does not arise. Giving retrospective effect will besides, complicate matters. Thirdly, it will hardly be possible to work out refunds to be made and the additional rent to be realised in case the orders are given retrospective effect.